

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग : २

देहरादून : दिनांक : १९ मार्च, २००७

विषय: मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल परिसर में अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष २००६-०७ में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-४२६/UHC/Admin.B/Const./२००६, दिनांक १४.२.२००७ एवं ४३०/UHC/Admin.B/Const./२००६, दिनांक १४.२.२००७ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्न तालिका के स्तम्भ-२ में उल्लिखित कार्य हेतु उनके समुख स्तम्भ-५ में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रु० १,८५,०००/- (एक लाख पचासी हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मूल आगणन धनराशि	टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में कैन्टीन ब्लॉक, एम०एल०ए० क्वार्टर्स कक्ष संख्या-२५ एवं डांडी हाउस में रंगाई-पुताई आदि का कार्य	८७,५००	८५,०००	८५,०००
2	मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में ब्रुकहिल एनैक्सी(महानिबन्धक आवास) में रंगाई-पुताई का कार्य	१,१२,०००	१,००,०००	१,००,०००
कुल स्वीकृत धनराशि				१,८५,०००

(रुपये एक लाख पचासी हजार मात्र)

- (१) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव में ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- (२) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (३) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा को स्थिरता में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (४) एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (५) निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकों दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय।

- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
  - (7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई हैं, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
  - (8) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय। इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा।
  - (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
  - (10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तदविषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अधिनियम से उत्तरदायी होगे।
  - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

3. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यवर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक “2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण” के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनदेश संख्या-88/XXVII(3)कार्य/2005, दिनांक 24.2.2005 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे।

भावदीय

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव

संख्या-७०-दो(२)/XXXVI(१)/२००६-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओवराय विलिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
  2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
  4. मुख्य अभियन्ता, स्टर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
  5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
  6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
  7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल।

आज्ञा स

2012

( एम०एम०सेमवाल )

अन सचिव ।

190307004